



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १०, अंक १८]

शुक्रवार, ऑक्टोबर ११, २०२४/आश्विन १९, शके १९४६ [पृष्ठे १५, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ३२

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

वित्त विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक

मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित ७ अक्टूबर २०२४।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. IX 2024.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA GOODS AND SERVICES
TAX ACT 2017.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ सन् २०२४।

महाराष्ट्र वस्तु और सेवा कर अधिनियम, २०१७ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, सन् २०१७ जिनके कारण उन्हें, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये महाराष्ट्र वस्तु और सेवा कर अधिनियम, २०१७ में का ४३। अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

अब, इसलिये, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम तथा
प्रारम्भण।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र वस्तु और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, २०२४ कहलाए।

(२) धारा १ तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(३) यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय शेष धाराएँ ऐसे दिनांक को भविष्यलक्षी या भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगी जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियत करें और इस अध्यादेश के विभिन्न उपबंधों के लिए, अलग-अलग दिनांक नियत किए जा सकेंगे और इस अध्यादेश के प्रारम्भण के लिए किन्हीं ऐसे उपबंध में किसी संदर्भ का उस उपबंध के प्रवृत्त होने के संदर्भ के रूप में अर्थ लगाया जायेगा।

सन् २०१७ का
महा. ४३ की
धारा २ में
संशोधन।

२. महाराष्ट्र वस्तु और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (जिसे इसमें आगे “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा २ के खण्ड (६१) के स्थान में, निम्न खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :—

सन् २०१७
का
महा. ४३।

“(६१) “निविष्टि सेवा वितरक” का तात्पर्य, वस्तु या सेवाओं या दोनों के ऐसे आपूर्तिकर्ता के कार्यालय से है, जो धारा २५ में निर्दिष्ट निविष्टि व्यक्तियों के लिए या उनकी ओर से धारा ९ की, उप-धारा (३) या उप-धारा (४) के अधीन कर के लिए दायी सेवाओं के संबंध में के बीजक समेत निविष्टि सेवाओं की प्राप्ति के लिये कर बीजक प्राप्त करता है और धारा २० में उपबंधित रीत्या, ऐसे बीजक के संबंध में निविष्टि कर ज़मा का वितरण करने के लिए दायी है ;”।

सन् २०१७ का
महा. ४३ की
धारा ९ में
संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ९ की, उप-धारा (१) में, “मानव उपभोग के लिए अल्कोहल युक्त मादक शराब” शब्दों के पश्चात्, “और मानव उपभोग के लिए अलकोहल युक्त मादक शराब के विनिर्माण के लिए उपयोगी किये जानेवाले असंक्रमित अतिरिक्त निष्प्रभावी अलकोहल या परिशोधित स्पिरिट” शब्द निविष्टि किए जायेंगे।

सन् २०१७ का
महा. ४३ की
धारा १० में
संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा १० की, उप-धारा (५) में, “धारा ७३ या धारा ७४” शब्दों और अंकों के पश्चात् “या धारा ७४क” शब्द, अंक और अक्षर निविष्टि किए जायेंगे।

सन् २०१७ का
महा. ४३ में धारा
११क का निवेशन।

५. मूल अधिनियम की धारा ११ के पश्चात्, निम्न धारा निविष्टि की जायेगी, अर्थात् :—

साधारण चलन के
प्रतिफल के रूप
में उद्ग्रहीत या
कम उद्ग्रहीत न
होनेवाले वस्तु एवं
सेवा कर वसूल
न करने के
अधिकार।

“११क. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि, —

(क) वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की किसी आपूर्ति पर राज्य कर के उद्ग्रहण (उसके उद्ग्रहण न करने समेत) संबंधित कोई प्रथा सामान्यतः प्रचलित थी या है ; और

(ख) ऐसी आपूर्ति, जहाँ—

(एक) जहाँ उक्त प्रथा के अनुसार राज्य कर नहीं लगाया गया था या उद्ग्रहीत नहीं किया गया है, के मामले में, राज्य कर के लिये पात्र थे या है ; या

(दो) उक्त प्रथा के अनुसरण में, जो राज्य कर की रकम उद्ग्रहीत था या उद्ग्रहीत की जा रही रकम राज्य कर से अधिक है तो सरकार, परिषद की सिफारिश पर, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि, ऐसी आपूर्तियों पर देय संपूर्ण राज्य कर या, यथास्थिति, ऐसी आपूर्तियों पर देय राज्य कर से अधिक है परंतु, उक्त प्रथा न होती तो उन आपूर्तियों के संबंध में अदायगी करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिसपर उक्त प्रथा के अनुसार राज्य कर उद्ग्रहीत नहीं किया गया था या उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा है या कम उद्ग्रहीत किया जा रहा है, के लिये दायी है तो अदा करने की आवश्यकता नहीं है।”।

६. मूल अधिनियम की धारा १३ की, उप-धारा (३), के,—

सन् २०१७ का
महा. ४३ की
धारा १३ में
संशोधन।

(१) खण्ड (ख) में “ प्रदायकर्ता द्वारा ” शब्दों के स्थान में, “ जहाँ प्रदायकर्ता द्वारा बीजक जारी करना आवश्यक है, के मामले में प्रदायकर्ता द्वारा ; या ” शब्द रखे जायेंगे ;

(२) खण्ड (ख) के पश्चात् निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा अर्थात् :—

(ग) जहाँ प्राप्तकर्ता द्वारा बीजक जारी करने का दिनांक में प्राप्त कर्ता द्वारा बीजक जारी किया है : ”।

(३) प्रथम परन्तु में, “ या खण्ड (ख) ” शब्दों, कोष्ठको या अक्षरों के पश्चात् “ या खण्ड (ग) ” शब्द, कोष्ठक या अक्षर निविष्ट किए जायेंगे ।

७. मूल अधिनियम की, धारा १६ की, उप-धारा (४), के पश्चात्, निम्न उप-धारा जोड़ी जायेगी और १ जुलाई २०१७ से जोड़ी समझी जायेगी, अर्थात् :—

सन् २०१७ का
महा. ४३ की
धारा १६ में
संशोधन।

“(५) उप-धारा (४) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० और २०२०-२१ से संबंधित वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति के लिए बीजक या नामे नोट के संबंध में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा ३९ के अधीन कोई विवरणी जो नवम्बर २०२१ के तीसरे दिन तक दायर की है, में निविष्टि कर जमा रकम लेने का हकदार होगा ।

(६) जहाँ रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण धारा २९ के अधीन रद्द किया गया है और तत्पश्चात्, रजिस्ट्रेशन का रद्दकरण या तो धारा ३० के अधीन किसी आदेश द्वारा या अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा दिये गए किसी आदेश के अनुसरण में पिछे लिये गये हैं, और जहाँ बीजक या नामे नोट के संबंध में निविष्टि कर जमा रकम का लाभ रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश के दिनांक पर, उप-धारा (४) के अधीन निर्बंधित नहीं किया गया हो तो उक्त व्यक्ति वस्तु या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए ऐसे बीजक या नामे नोट के संबंध में निविष्टि कर जमा रकम लेने का हकदार होगा, धारा ३९ के अधीन विवरणी में,—

(एक) अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के नवम्बर के तीसरे दिन तक दाखिल की है जिसका ऐसा बीजक या नामे नोट सुसंगत वार्षिक विवरण से संबंधित है या विरचित है, जो भी पहले हो ; या

(दो) रजिस्ट्रीकरण को रद्दकरण के दिनांक से अवधि के लिए या, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रभावी होने के दिनांक से रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण का पीछे लिये गये आदेश के दिनांक तक जहाँ ऐसी विवरणी रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का पीछे लिये गये आदेश के दिनांक से तीस दिनों के भीतर दाखिल की है, जो भी बाद का हो, निविष्टि कर जमा रकम लेने का हकदार होगा । ”।

८. मूल अधिनियम की धारा १७ की, उप-धारा (५) के खण्ड (एक) में, “ धाराएँ ७४, १२९ और १३० ” शब्दों और अंकों के स्थान में “ वित्तीय वर्ष २०२३-२४ तक के किन्ही अवधि के संबंध में धारा ७४ ” शब्द और अंक रखे जायेंगे ।

सन् २०१७ का
महा. ४३ की
धारा १७ में
संशोधन।

निविष्टि
सेवा
वितरक
द्वारा जमा
रकम
वितरित
करने की
रीति।

९. मूल अधिनियम की धारा २० के स्थान में, निम्न धारा रखी जायेगी, अर्थात् :—

सन् २०१७ का
महा. ४३ की
धारा २० का
प्रतिस्थापन ।

“(२०). (१) वस्तुएँ या सेवाएँ या दोनों के आपूर्तिकर्ता का कोई कार्यालय जो धारा २५ में निर्देशित विशिष्ट व्यक्तियों के लिए या उनकी ओर से धारा ९ की, उप-धारा (३) या उप-धारा (४) के अधीन कर के लिए दायी सेवाओं के संबंध में बीजक समेत निविष्टि सेवाओं की प्राप्ति के जरिए कर बीजक प्राप्त करता है, धारा २४ के खण्ड (आठ) के अधीन निविष्टि सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकरण करना आवश्यक होगा और ऐसे बीजकों के संबंध में निविष्टि कर जमा रकम वितरित करेगा।

(२) निविष्टि सेवा वितरक उसके द्वारा प्राप्त बीजकों पर प्रभारित राज्य कर या एकीकृत कर के जमा रकम को वितरित करेगा जिसमें धारा ९ की उप-धारा (३) या उप-धारा (४) के अधीन कर के उद्ग्रहण के अध्यक्षीन सेवाओं के संबंध में राज्य कर या एकीकृत कर की जमा रकम समेत उसका भूगतान उक्त निविष्टि सेवा वितरक के रूप में उसी राज्य में रजिस्ट्रीकृत विशिष्ट व्यक्ति द्वारा किया गया हो, के भीतर और ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अध्यक्षीन वितरित किया जायेगा ।

(३) राज्य कर का जमा रकम राज्य कर या एकीकृत कर के रूप में और एकीकृत कर यह एकीकृत कर या राज्य कर के रूप में, निविष्टि कर जमा रकम की रकम से अंतर्विष्टि दस्तावेज जारी करके ऐसी रित्या वितरित किया जायेगा जैसा कि विहित किया जाए । ” ।

सन् २०१७ का
महा. ४३ की
धारा २१ में
संशोधन ।
१०. मूल अधिनियम की धारा २१, में, “धारा ७३ या धारा ७४” शब्दों और अंको के पश्चात् “या धारा ७४क” शब्द, अंक और अक्षर निविष्टि किए जायेंगे ।

सन् २०१७ का
महा. ४३ की
धारा ३० में
संशोधन ।
११. मूल अधिनियम की धारा ३० के परंतुक के पश्चात् निम्न परंतुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

“परंतु आगे यह कि, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण करने का ऐसा पिछे लेना जैसा कि विहित किया जाए ऐसे शर्तों और निर्बंधनों के अध्वधीन होगा ।” ।

सन् २०१७ का
महा. ४३ की
धारा ३१ में
संशोधन ।
१२. मूल अधिनियम की धारा ३१ की,—
(क) उप-धारा (३) के खण्ड (च) में, “धारा ९ के रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति शब्दों और अंकों के पश्चात्, “जैसा की विहित किया जाए ऐसी अवधि के भीतर ” शब्द निविष्टि किए जायेंगे ;

(ख) खण्ड (छ) के पश्चात् निम्न **स्पष्टीकरण** निविष्टि किया जायेगा, अर्थात् :—

“**स्पष्टीकरण.**—खण्ड (च) के प्रयोजनों के लिए “आपूर्तिकर्ता जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है ” “अभिव्यक्ति में, जो धारा ५१ के अधीन कर की कटौती के प्रयोजन के लिए केवल वह से रजिस्ट्रीकृत है ऐसा आपूर्तिकर्ता सम्मिलित होगा।” ।

सन् २०१७ का
महा. ४३ की
धारा ३५ में
संशोधन ।
१३. मूल अधिनियम की धारा ३५ की, उप-धारा (६), में, “धारा ७३ या धारा ७४” शब्दों और अंकों के पश्चात् “या धारा ७४क” शब्द, अंक और अक्षर निविष्टि किए जायेंगे ।

सन् २०१७ का
महा. ४३ की
धारा ३९ में
संशोधन ।
१४. मूल कर अधिनियम की धारा ३९ की, उप-धारा (३) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जायेगी, अर्थात् :—

“ (३) धारा ५१ के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए आवश्यक प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जैसा कि विहित किया जाए ऐसे प्ररूप और रीत्या तथा ऐसे समय के भीतर उस महीने के दौरान जिस महीने में कटौती की गई के कटौती के प्रत्येक कैलेंडर महीने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में विवरणी प्रस्तुत करेगा :

परंतु, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कैलेंडर महीने के लिए चाहे उक्त महीने के दौरान कोई कटौती की है या नहीं की है, विवरणी प्रस्तुत करेगा ।” ।

सन् २०१७ का
महा. ४३ की
धारा ४९ में
संशोधन ।
१५. मूल अधिनियम की धारा ४९ की, उप-धारा (८), के, खण्ड (ग) में, “धारा ७३ या धारा ७४” शब्दों और अंकों के पश्चात् “या धारा ७४क” शब्द, अंक और अक्षर जोड़े जायेंगे ।

सन् २०१७ का
महा. ४३ की
धारा ५० में
संशोधन ।
१६. मूल अधिनियम की धारा ५० की, उप-धारा (१), के परंतुक में “धारा ७३ या धारा ७४” शब्दों और अंकों के पश्चात् “या धारा ७४क” शब्द, अंक और अक्षर निविष्टि किये जायेंगे ।

सन् २०१७ का
महा. ४३ की
धारा ५१ में
संशोधन ।
१७. मूल अधिनियम की धारा ५१ की, उप-धारा (७) में, “धारा ७३ या धारा ७४” शब्दों और अंकों के पश्चात्, “या धारा ७४क” शब्द, अंक और अक्षर निविष्टि किये जायेंगे ।

१८. मूल अधिनियम की धारा ५४ की,—

सन् २०१७ का
महा. ४३ की
धारा ५४ में
संशोधन।

(१) उप-धारा (३) के द्वितीय परंतुक अपमार्जित किया जायेगा ;

(२) उप-धारा (१४) के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पूर्व निम्न उप-धारा निविष्ट की जायेगी,
अर्थात् :—

“ (१५) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शून्य दर आपूर्ति के कारण उपयोग न किए गए निविष्टि कर जमा रकम या वस्तुओं के शून्य दरवाली वस्तुओं की आपूर्ति के कारण अदा किये गये एकीकृत कर की कोई वापसी की अनुमति नहीं दी जायेगी जहाँ ऐसी शून्य दरवाली वस्तुओं की आपूर्ति निर्यात शुल्क के अध्याधीन है ।”।

१९. मूल अधिनियम की धारा ६१ की, उप-धारा (३) में, “ धारा ७३ या धारा ७४ ” शब्दों और अंकों के पश्चात्, “ या धारा ७४क ” शब्द, अंक और अक्षर जोड़े जायेंगे ।

सन् २०१७ का
महा. ४३ की धारा
६१में संशोधन।

२०. मूल अधिनियम की धारा ६२ की, उप-धारा (१) में, “ धारा ७३ या धारा ७४ ” शब्दों और अंकों के पश्चात्, “ या धारा ७४क ” शब्द, अंक या अक्षर निविष्ट किए जायेंगे।

सन् २०१७ का
४३ की धारा ६२
में संशोधन।

२१. मूल अधिनियम की धारा ६३ में, “ धारा ७३ या धारा ७४ ” शब्दों और अंकों के पश्चात्, या “ धारा ७४ क ” शब्द, अंक और अक्षर निविष्ट किए जायेंगे ।

सन् २०१७ का
महा. ४३ की धारा
६३ में संशोधन।

२२. मूल अधिनियम की धारा ६४ की, उप-धारा (२) में, “ धारा ७३ या धारा ७४ ”, शब्दों और अंकों के पश्चात्, “ या धारा ७४ क ” शब्द, अंक और अक्षर जोड़े जायेंगे।

सन् २०१७ का
महा. ४३ की धारा
६४ में संशोधन ।

२३. मूल अधिनियम की धारा ६५ की, उप-धारा (७) में, “ धारा ७३ या धारा ७४ ” शब्दों और अंकों के पश्चात्, “ या धारा ७४ क ” शब्द, अंक और अक्षर जोड़े जायेंगे।

सन् २०१७ का
महा. ४३ की धारा
६५ में संशोधन ।

२४. मूल अधिनियम की धारा ६६ की, उप-धारा (६) में, “ धारा ७३ या धारा ७४ ” शब्दों और अंकों के पश्चात्, “ या धारा ७४ क ” शब्द, अंक और अक्षर जोड़े जायेंगे।

सन् २०१७ का
महा. ४३ की धारा
६६ में संशोधन ।

२५. मूल अधिनियम की धारा ७० की, उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्न उप-धारा निविष्ट की जायेगी,
अर्थात् :—

सन् २०१७ का
महा. ४३ की धारा
७० में संशोधन ।

“ (१क) उप-धारा (१) के अधीन समन किये गये सभी व्यक्ति या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जैसा कि अधिकारी निर्देश दे उपस्थित होने के लिये बाध्यकारी होंगे और इसप्रकार उपस्थित रहनेवाला व्यक्ति की साक्ष्य की जाँच के दौरान सत्य कथन करेगा या कथन करेगा या ऐसे दस्तावेज और अन्य वस्तुएँ प्रस्तुत करेगा जिनकी आवश्यकता हो। ”।

२६. मूल अधिनियम की धारा ७३ के,—

सन् २०१७ का
महा. ४३ की
धारा ७३ में
संशोधन ।

(१) पार्श्व टिप्पणी में, “ कर का निर्धारण ” शब्दों के पश्चात्, “ वित्तिय वर्ष २०२३-२४ तक की अवधि से संबंधित ” शब्द और अंक निविष्ट किए जायेंगे ;

(२) उप-धारा (११) के पश्चात्, निम्न उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात् :—

“ (१२) इस धारा के उपबंध वित्तिय वर्ष २०२३-२४ तक की अवधि से संबंधित कर का अवधारण करने के लिए लागू होंगे। ”।

सन् २०१७ का
महा. ४३ की धारा
७४ में संशोधन।

२७. मूल अधिनियम की धारा ७४ के, —

(१) पार्श्व टिप्पणी में, “ कर का अवधारण ” शब्दों के पश्चात्, “ वित्तीय वर्ष २०२३-२४ तक की अवधि से संबंधित ” शब्द निविष्ट किए जायेंगे ;

(२) उप-धारा (११) के पश्चात्, और स्पष्टीकरण १ के पूर्व, निम्न उप-धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

“ (१२) इस धारा के उपबंध, वित्तीय वर्ष २०२३-२४ तक की अवधि से संबंधित कर का निर्धारण करने के लिए लागू होंगे। ” । ;

(३) स्पष्टीकरण २ अपमार्जित किया जायेगा ।

सन् २०१७ का
महा. ४३ में धारा
७४क का
निवेशन।

२८. मूल अधिनियम की धारा ७४ के पश्चात्, निम्न धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

“ ७४ क. (१) जहाँ समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि, कोई कर अदा नहीं किया गया है या कम अदा किया गया है या गलत तरीके से प्रतिदाय किया है या जहाँ निविष्टि कर ज़मा रकम का गलत तरीके से लाभ लिया गया है या उसका उपयोग किया गया है, तो उस व्यक्ति को नोटिस देगा जो कर का भुगतान नहीं किया गया है या कम अदा किया गया है या जिसे गलत तरीके से प्रतिदाय किया गया है या जिसने निविष्टि कर ज़मा रकम गलत तरीके से ली गयी है या उसका उपयोग किया है तो, धारा ५० के अधीन उसपर देय ब्याज के साथ नोटीस में विनिर्दिष्ट रकम और इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति की रकम वह क्यों न अदा करे के बारे में कारण दर्शाने की अपेक्षा करते हुए नोटीस तामिल करेगा :

परंतु, यदि वह कर जिसका वित्तीय वर्ष में भुगतान नहीं किया गया है या कम अदा किया गया है या गलत तरीके से प्रतिदाय किया गया है या जहाँ निविष्टि कर ज़मा रकम को गलत तरीके से लिया गया है या उसका उपयोग किया गया है वह रकम एक हजार रूपयों से कम है, तो यह नोटीस जारी नहीं की जायेगी ।

(२) समुचित अधिकारी, उस वित्तीय वर्ष, जिस वर्ष का कर अदा नहीं किया गया है या कम अदा किया गया है या निविष्टि कर ज़मा रकम गलत तरीके से लिया गया है या उपयोग किया गया है, उस वित्तीय वर्ष से संबंधित वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के देय दिनांक से ब्यालिस महीने के भीतर प्रतिदाय दिये गये उप-धारा (१) के अधीन नोटीस जारी करेगा ।

(३) उप-धारा (१) के अधीन किसी अवधि के लिए नोटीस जारी किया गया है उस बारे में समुचित अधिकारी कर के लिये उत्तरदायी व्यक्ति पर, उप-धारा (१) के अधीन आनेवाली कर अवधि से अन्य ऐसी अवधि के लिये कर अदा न किये गये या कम अदा किये गये या गलती से प्रतिदाय किये गये या गलती से लिये गये या उपयोग किये गये निविष्टि कर ज़मा रकम कर ब्यौरेवार अन्तर्विष्ट विवरण तामिल करेगा ।

(४) ऐसे विवरण की तामिल करने पर उप-धारा (१) के अधीन ऐसे व्यक्ति पर नोटीस तामिल की गई समझी जायेगी, जो इस शर्त के अधीन कि, उप-धारा (१) के अधीन आनेवाली ऐसी कर अवधियों से अन्य ऐसी कर अवधियों के लिए जिन आधारों पर विश्वास किया गया है वे वहीं हैं जो पूर्वतर नोटीस में उल्लिखित है ।

(५) जहाँ कोई कर, जो अदा नहीं किया गया है या कम अदा किया गया है या गलत तरीके से प्रतिदाय किया गया है, या जहाँ निविष्टि कर ज़मा रकम का गलत तरीके से ली गयी है या उपयोग किया है, के मामले में शास्ति,—

(एक) कर से बचने के लिए धोखाधड़ी या जानबूझकर किया गया गलत बयान या तथ्यों को छिपाने के अलावा किसी अन्य कारण से ऐसे व्यक्ति से देय कर के दस प्रतिशत या दस हजार रुपये जो भी अधिक हो, के समान होगा ;

(दो) कर से बचने के लिए धोखाधड़ी या कोई जानबूझकर किया गया गलत बयान या तथ्यों को छिपाने के कारण ऐसे व्यक्ति से देय कर के समान होगा ;

(६) समुचित अधिकारी अभ्यावेदन का विचार-विमर्श करने के पश्चात् कर प्रभार्य व्यक्ति यदि कोई हो, ऐसे व्यक्ति से देय कर की रकम, ब्याज और शास्ति की रकम विनिश्चित करेगा और वैसा आदेश जारी करेगा ।

(७) समुचित अधिकारी उप-धारा (२) में विनिर्दिष्ट नोटीस के जारी करने दिनांक से बारह महीने के भीतर उप-धारा (६) के अधीन आदेश जारी करेगा :

परंतु, जहाँ समुचित अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आदेश जारी करने के लिए समर्थ नहीं हैं वहाँ आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की श्रेणी के वरिष्ठ परंतु राज्य संयुक्त कर आयुक्त की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी से न हो, उप-धारा (६) के अधीन आदेश के जारी होने में विलंब के लिए कारणों ध्यान में रखते हुए, जिसे विनिर्दिष्ट अवधि के अवसित होने के पूर्व लिखित में अभिलिखित करते हुए उक्त अवधि को अधिकतम छह महीने के लिये आगे बढ़ा सकेगा ।

(८) कर से प्रभार्य व्यक्ति जहाँ कोई कर अदा नहीं किया गया है या कम कर अदा किया गया है या गलत तरीके से प्रतिदाय किया गया है या जहाँ निविष्टि कर ज़मा रकम गलत तरीके से ली गयी है या कर से बचने के लिए धोखाधड़ी या जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छिपाने के किसी कारण के अलावा किसी अन्य कारण से उपयोग किया गया है, वह—

(एक) उप-धारा (१) के अधीन नोटीस तामिल करने के पूर्व, ऐसे कर के अपने स्वअभिनश्चयन के आधार पर या समुचित प्राधिकारी द्वारा यथा अभिनश्चयीत कर की रकम धारा ५० के अधीन देय ब्याज के साथ की रकम अदा कर सकेगा, और ऐसे अदायगी का लिखित रूप में समुचित अधिकारी को जानकारी देगा, और समुचित अधिकारी, ऐसी जानकारी की प्राप्ति पर इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन इस प्रकार अदा कर या या देय कोई शास्ति के संबंध में, उप-धारा (१) के अधीन कोई नोटीस या, यथास्थिति, उप-धारा (३) के अधीन कोई विवरणी तामिल नहीं करेगा ;

(दो) धारा ५० के अधीन देय ब्याज के साथ उक्त कर कारण दर्शाओ नोटीस के जारी होने के दिनांक से साठ दिनों के भीतर अदा कर सकेगा, और इसप्रकार कर अदा करने पर कोई शास्ति देय नहीं होगी तथा उक्त नोटीस के संबंध में सभी कार्यवाहियाँ समाप्त हो चुकी ऐसा समझा जायेगा ।

(९) कर से प्रभार्य व्यक्ति, जहाँ कोई कर अदा नहीं किया गया है या कम अदा किया गया है या गलती से कर का प्रतिदाय किया गया है या निविष्टि कर ज़मा रकम गलत तरीके से ली गयी है या कर से बचने के लिए धोखाधड़ी या जानबूझकर गलत बयान किया गया है या तथ्यों को छिपाया गया है तो करप्रभार्य व्यक्ति,—

(एक) उप-धारा (१) के अधीन नोटीस तामिल करने के पूर्व, धारा ५० के अधीन देय ब्याज के साथ कर की रकम और ऐसे कर के उसके स्वअभिनश्चयन या समुचित अधिकारी द्वारा यथा अभिनश्चयन के आधार पर कर पर ऐसे कर के पचास प्रतिशत की समान शास्ति अदा कर सकेगा

और ऐसी अदायगी का लिखित में समुचित अधिकारी को जानकारी देगा, तथा ऐसी जानकारी की प्राप्ति पर समुचित अधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन इस प्रकार अदा कर या देय शास्ति के संबंध में उप-धारा (१) के अधीन कोई नोटीस तामिल नहीं करेगा ;

(दो) धारा ५० के अधीन देय ब्याज के साथ उक्त कर अदा करेगा और सूचना जारी करने के साठ दिनों के भीतर ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की समान शास्ति की अदायगी करेगा, और इस प्रकार अदायगी करने पर, उक्त नोटीस के संबंध में सभी कार्यवाहियाँ की गई है ऐसा समझा जायेगा ।

(तीन) धारा ५० के अधीन समतुल्य उसपर देय ब्याज के साथ कर अदा करेगा तथा ऐसे कर के पचास प्रतिशत की समतुल्य शास्ति अदा करने के आदेश की संसूचना के साठ दिनों के भीतर अदा करेगा और इसप्रकार अदा करने पर उक्त नोटीस के संबंध में सभी कार्यवाहियाँ समाप्त हो गयी है ऐसा समझा जायेगा ।

(१०) जहाँ समुचित अधिकारी की राय यह है कि, उप-धारा (८) के खण्ड (एक) या उप-धारा (९) के खण्ड (एक) के अधीन अदा की गई रकम वास्तविक में देय रकम से कम है, वहाँ ऐसी रकम के संबंध में उप-धारा (१) में यथा उपबंधित नोटीस जारी करने की कार्यवाही करेगा जो वास्तव में देय रकम से कम है ।

(११) उप-धारा (८) के खण्ड (एक) या खण्ड (दो) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उप-धारा (५) के खण्ड (एक) के अधीन शास्ति देय होगी वहाँ स्व-निर्धारित कर की कोई रकम या कर के रूप में संग्रहीत कोई रकम ऐसे कर के देय दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर अदा नहीं की गई है ।

(१२) इस धारा के उपबंध वित्तीय वर्ष २०२४-२५ से संबंधित कर का विनिश्चयन करने के लिए लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण १.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(एक) “उक्त नोटीस के संबंध में सभी कार्यवाहियाँ” अभिव्यक्ति में धारा १३२ के अधीन की कार्यवाहियाँ सम्मिलित नहीं होगी ;

(दो) जहाँ समान कार्यवाहियों के अधीन नोटिस कर अदा करने के लिये दायी मुख्य व्यक्ति और कुछ अन्य व्यक्तियों को जारी की गयी है और मुख्य व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कार्यवाहियाँ इस धारा के अधीन समाप्त की गयी है, के बारे में धारा १२२ और १२५ के अधीन शास्ति अदा करने के लिये दायी सभी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाहियाँ समाप्त हुई है ऐसा समझा जायेगा ।

स्पष्टीकरण (२).—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए “दमन” अभिव्यक्ति का तात्पर्य, कोई करादेय व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाए नियमों के अधीन प्रस्तुत विवरण, कथन, रिपोर्ट या कोई अन्य दस्तावेज में उन तथ्यों या जानकारी की घोषणा घोषित करने की आवश्यकता होती है, वह तथ्यों या जानकारी की घोषणा न करने, या समुचित अधिकारी द्वारा, उसे लिखित में किसी जानकारी के लिए पूछने पर उसे प्रस्तुत करने में असफल होता है, से है ।”।

सन् २०१७ का
महा. ४३ की
धारा ७५ में
संशोधन ।

२९. मूल अधिनियम की धारा ७५ की,—

(१) उप-धारा (१) में, “धारा ७४” शब्द और अंकों के पश्चात्, “या धारा ७४-क की, उप-धारा (२) और (७)” में शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर निविष्ट किए जायेंगे ;

(२) उप-धारा (२) पश्चात् निम्न उप-धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात्, :—

“(२क) जहाँ कोई अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है कि, धारा ७४क की उप-धारा (५) के, खण्ड (दो) के अधीन की शास्ति इस कारण लगाने योग्य नहीं है कि, कर से बचने के लिए धोखाधड़ी या जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने का आरोप उस व्यक्ति के विरुद्ध सिद्ध नहीं हुआ है जिसे यह नोटीस जारी किया गया था । वहाँ ऐसे व्यक्ति द्वारा धारा ७४क की, उप-धारा (५) के खण्ड (एक) के अधीन ऐसी शास्ति देय होगी ।”;

(३) उप-धारा (१०) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जायेगी, अर्थात्, :-

“(१०) न्यायनिर्णयन की कार्यवाहियाँ समाप्त हो गई ऐसा समझा जायेगा, यदि आदेश धारा ७३ की, उप-धारा (१०) या धारा ७४ की, उप-धारा (१०) या धारा ७४क की, उप-धारा (७) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जारी नहीं हुआ है।” ;

(४) उप-धारा (११) में, “धारा ७४” शब्द और अंकों के पश्चात् “या धारा ७४क की, उप-धारा (७)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर निविष्ट किये जायेंगे ;

(५) उप-धारा (१२) में, “धारा ७३ या धारा ७४” शब्दों और अंकों के पश्चात्, “या धारा ७४क” शब्द, अंक और अक्षर निविष्ट किए जायेंगे ;

(छह) उप-धारा (१३) में, “धारा ७३ या धारा ७४” शब्दों और अंकों के पश्चात्, “या धारा ७४क” शब्द, अंक और अक्षर निविष्ट किए जायेंगे ।

३०. मूल अधिनियम की धारा १०४ की, उप-धारा (१) के **स्पष्टीकरण** में, “धारा ७४” शब्द और अंकों के पश्चात्, “या ७४क की, उप-धारा (२) और (७)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर जोड़े जायेंगे ।

सन् २०१७ का
महा. ४३ की
धारा १०४ में
संशोधन ।

३१. मूल अधिनियम की धारा १०७ की,—

(एक) उप-धारा (६) के खण्ड (ख) में, “पच्चीस करोड़” शब्दों के स्थान में “बीस करोड़” शब्द रखे जायेंगे ;

सन् २०१७ का
महा. ४३ की
धारा १०७ में
संशोधन ।

(दो) उप-धारा (११) के द्वितीय परंतुक में, “धारा ७३ या धारा ७४” शब्दों और अंकों के पश्चात्, “या धारा ७४क” शब्द, अंक और अक्षर जोड़े जायेंगे ।

३२. मूल अधिनियम की धारा १०९ में, “पुनरीक्षण प्राधिकारी” शब्दों के पश्चात् “या धारा १७१ की, उप-धारा (२) में निर्दिष्ट मामलों की जाँच या न्यायनिर्णयन करने के लिये, यदि उक्त धारा के अधीन ऐसा अधिसूचित किया गया हो” शब्द निविष्ट किये जायेंगे ।

सन् २०१७ का
महा. ४३ की
धारा १०९ में
संशोधन ।

३३. मूल अधिनियम की धारा ११२ में,—

(१) उप-धारा (१) में, “अपील किये जानेवाले व्यक्ति को जिस आदेश के विरुद्ध अपील की जानेवाली है, ऐसा आदेश उसे संसूचित किये जाने के दिनांक से” शब्दों के पश्चात्, “या वह दिनांक जिसे इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए, परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, जो भी बाद का हो,” शब्द निविष्ट किए जायेंगे, और १ अगस्त २०२४ से निविष्ट किये गये समझे जायेंगे ;

सन् २०१७ का
महा. ४३ की
धारा ११२ में
संशोधन ।

(२) उप-धारा (३) में, “उस दिनांक से जिस पर उक्त आदेश पारित किया गया है” शब्दों के पश्चात्, “या ; वह दिनांक जिसे इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष आवेदन दाखिल करने के प्रयोजन के लिए परिषद की सिफारिश पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए,” शब्द निविष्ट किए जायेंगे और १ अगस्त २०२४ से निविष्ट किये गये समझे जायेंगे ;

(३) उप-धारा (६) में, “उप-धारा (१) में निर्दिष्ट अवधि अवसित होने के पश्चात्” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात्, “या उप-धारा (३) में निर्दिष्ट अवधि अवसित होने पश्चात् तीन महीने के भीतर आवेदन दाखिल करने की अनुमति” शब्द, कोष्ठक और अंक निविष्ट किए जायेंगे ;

(४) उप-धारा (८) के खण्ड (ख) में,—

(क) “बीस प्रतिशत” शब्दों के स्थान में, “दस प्रतिशत” शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) “पचास करोड़ रुपयों” शब्दों के स्थान में, “बीस करोड़ रुपयों” शब्द रखे जायेंगे ।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा १२२ में संशोधन । **३४.** मूल अधिनियम की धारा १२२ की, उप-धारा (१ख) में, “कोई इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक जो” शब्दों के स्थान में, “कोई इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक, जो धारा ५२ के अधीन स्रोत पर कर संग्रहण करने के लिए दायी है” शब्द और अंक रखे जायेंगे और १ अक्टूबर २०२३ से रखी गयी समझी जायेगी ।

सन् २०१७ का महा. ४३ में धारा १२२ का निवेशन । **३५.** (१) मूल अधिनियम की धारा १२२ के पश्चात्, निम्न धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

विशेष प्रक्रिया के अनुसार वस्तुओं के विनिर्माण में उपयोगी कतिपय मशीनों का रजिस्ट्रीकरण करने में असफल होने पर शास्ति । **“१२२क.** इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ कोई व्यक्ति, जो वस्तुओं के विनिर्माण में जुड़े है जिसके संबंध में मशीनों का रजिस्ट्रेशन करने से संबंधित कोई विशेष प्रक्रिया धारा १४८ के अधीन अधिसूचित की गई है, उक्त विशेष प्रक्रिया के उल्लंघन में कार्य करता है, तो वह अध्याय पंद्रह या इस अध्याय के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन कोई शास्ति जो उसके द्वारा अदा की है या देय है, के अतिरिक्त, इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत न किए गए प्रत्येक मशीन के लिए एक लाख रुपयों की रकम के समान शास्ति अदा करने के लिए दायी होगा ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन शास्ति के अतिरिक्त, इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत न किया गया प्रत्येक मशीन अभिग्रहण करने और ज़ब्त करने के लिए दायी होगा :

परंतु, ऐसा मशीन ज़ब्त नहीं की जायेगी,—

(क) इस प्रकार अधिरोपित शास्ति अदा की है ; और

(ख) ऐसे मशीन का रजिस्ट्रीकरण, शास्ति के आदेश की संसूचना की प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर विशेष प्रक्रिया के अनुसरण में की है ।”।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा १२७ में संशोधन । **३६.** मूल अधिनियम की धारा १२७ में, “धारा ७३ या धारा ७४” शब्दों और अंको के पश्चात्, “या धारा ७४क” शब्द, अंक और अक्षर निविष्ट किए जायेंगे ।

सन् २०१७ का महा. ४३ में नई धारा १२८क का निवेशन । **३७.** मूल अधिनियम की धारा १२८ के पश्चात्, निम्न धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

कतिपय कर अवधियों के किये धारा ७३ के अधीन उठाई गयी मांगों से संबंधित ब्याज या शास्ति या दोनों से छूट । **“१२८क.** (१) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उल्लंघन में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ कर की कोई रकम प्रभार्य व्यक्ति द्वारा देय है के अनुसरण में,—

(क) धारा ७३ की, उप-धारा (१) के अधीन जारी की गयी नोटीस या धारा ७३ की, उप-धारा (३) के अधीन जारी की गयी विवरणी और जहाँ धारा ७३ की, उप-धारा (९) के अधीन कोई आदेश जारी नहीं किया है ; या

(ख) धारा ७३ की, उप-धारा (९) के अधीन पारित कोई आदेश और जहाँ धारा १०७ की, उप-धारा (११) या धारा १०८ की, उप-धारा (१) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया है ; या

(ग) धारा १०७ की, उप-धारा (११) या धारा १०८ की, उप-धारा (१) के अधीन पारित कोई आदेश और जहाँ धारा ११३ की, उप-धारा (१) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया है,

१ जुलाई २०१७ से ३१ मार्च २०२० की अवधि से या उसके भाग संबंधित है, और के अनुसरण में संदाय किया जायेगा और उक्त व्यक्ति, परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा जिसे अधिसूचित किया जाए ऐसे दिनांक पर या के पूर्व खण्ड (क), खण्ड (ख) या, यथास्थिति, खण्ड (ग) में निर्दिष्ट नोटीस या विवरणी या आदेश के अनुसार देय कर की संपूर्ण रकम अदा करेगा, धारा ५० के अधीन कोई ब्याज और इस अधिनियम के अधीन कोई शास्ति देय नहीं होगी और उक्त नोटीस, विवरणी या, यथास्थिति, आदेश के संबंध में सभी कार्यवाहियाँ जैसा कि विहित किया जाए, ऐसी शर्तों के अध्वधीन समाप्त हुई ऐसा समझा जायेगा :

परंतु, जहाँ धारा ७४ की, उप-धारा (१) के अधीन नोटीस जारी की गयी है और आदेश धारा ७५ की, उप-धारा (२) के उपबंधों के अनुसरण में अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के निर्देशन के अनुसरण में समुचित अधिकारी द्वारा पारित है या पारित किए जाने की आवश्यकता है, उक्त नोटीस या आदेश इस उप-धारा के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट नोटीस या, यथास्थिति, आदेश के रूप में समझा जायेगा :

परंतु आगे यह कि, जहाँ कोई कार्यवाहियाँ, खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट आदेश के विरुद्ध या प्रथम परंतुक में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के निदेशन के विरुद्ध धारा १०७ की, उप-धारा (३) या धारा ११२ की, उप-धारा (३) के अधीन आवेदन दायर किया है या धारा ११७ की, उप-धारा (१) या धारा ११८ की, उप-धारा (१) के अधीन राज्य कर अधिकारी द्वारा अपील दायर किया गया है या धारा १०८ की, उप-धारा (१) के अधीन शुरू की है के मामले में, इस शर्त के अध्वधीन कि, उक्त व्यक्ति, अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय या, यथास्थिति, पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश के अनुसरण में, उक्त आदेश के दिनांक से तीन महीने के भीतर देय कर की अतिरिक्त रकम, यदि कोई है, तो अदा करेगा, इस उप-धारा के अधीन की कार्यवाहियाँ समाप्त होगी :

परंतु, यह भी कि, जहाँ ऐसा ब्याज और शास्ति पहले से ही अदा की गई है तो उसका प्रतिदाय उपलब्ध नहीं होगा ।

(२) उप-धारा (१) में अंतर्विष्ट कोई बात, गलत प्रतिदाय के कारण व्यक्ति द्वारा देय कोई रकम के संबंध में लागू नहीं होगी ।

(३) उप-धारा (१) में अंतर्विष्ट कोई बात, जहाँ उक्त व्यक्ति द्वारा दायर अपील या रिट याचिका अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या, यथास्थिति, न्यायालय के समक्ष लंबित है, और उप-धारा (१) के अधीन अधिसूचित दिनांक पर या के पूर्व उक्त व्यक्ति द्वारा वापस नहीं की गई है के मामले के संबंध में लागू नहीं होगी ।

(४) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ उप-धारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट कोई रकम संदत्त की गई है और उक्त उप-धारा के अधीन कार्यवाहियाँ समाप्त की गई ऐसा समझा गया है तो उप-धारा (१) के खण्ड (ख) या, यथास्थिति, खण्ड (ग) में निर्दिष्ट आदेश के विरुद्ध धारा १०७ की उप-धारा (१) या धारा ११२ की, उप-धारा (१) के अधीन कोई अपील दायर नहीं की जायेगी ।”।

३८. मूल अधिनियम की धारा १७१ की,—

(१) उप-धारा (२) में निम्न परंतुक और **स्पष्टीकरण** जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

“परन्तु, सरकार परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा वह दिनांक विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिसे सन् २०१७ का उक्त प्राधिकारी रजिस्ट्रिकृत व्यक्ति द्वारा चाहे वह निविष्टि कर जमा रकम का लाभ उठाने के परीक्षण महा. ४३ की के लिये किसी अनुरोध को स्वीकार नहीं करेगा या वास्तव में उसके द्वारा आपूर्ति की गयी वस्तुओं धारा १७१ में या सेवाओं या दोनों की मूल्य में समानुपातिक कटौती कर दर में कटौती का नतिजा है । संशोधन ।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिये “परिक्षण करने के लिये अनुरोध” का तात्पर्य किसी रजिस्ट्रिकृत व्यक्ति द्वारा चाहे वह निविष्टि कर ज़मा रकम या कर दर में कटौती के परिणाम स्वरूप परीक्षण करने के लिए किसी आवेदक के अनुरोध पर दायर लिखित आवेदन उसके द्वारा की गयी आपूर्ति वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के मूल्य में समानुपातिक कटौती का नतीजा है, से है।”;

(२) विद्यमान **स्पष्टीकरण** उसके स्पष्टीकरण १ के रूप में पुनःक्रमांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनःक्रमांकित **स्पष्टीकरण** १ के पश्चात्, निम्न **स्पष्टीकरण** जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

“**स्पष्टीकरण २.**—इस धारा के प्रयोजन के लिए, “प्राधिकरण” अभिव्यक्ति में अपील अधिकरण सम्मिलित है।”।

सन् २०१७ का
महा. ४३ की
अनुसूचि तीन में
संशोधन।

३९. मूल अधिनियम से संलग्न अनुसूचि तीन में परिच्छेद ८ के पश्चात् और **स्पष्टीकरण** १ के पूर्व निम्न परिच्छेद जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

“९. सह-बीमा करारों में सह-बीमा अधिमूल्य में बीमाकृत को मुख्य बीमाकर्ता और सह-बीमाकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से आपूर्ति की गई बीमा सेवाओं के लिए मुख्य बीमाकर्ता द्वारा सह-बीमाकर्ता को सह-बीमा अधिमूल्य के बंटवारे की गतिविधि, इस शर्त के अध्वधीन कि, मुख्य बीमाकर्ता बीमाकृत व्यक्ति द्वारा अदा किए गए अधिमूल्य की संपूर्ण रकम पर केंद्रीय कर, राज्य कर, संघराज्य क्षेत्र कर और एकीकृत कर अदा कर सकेगा।

१०. बीमाकर्ता द्वारा पुनर्बीमाकर्ता को दी गई सेवाएँ, जिनके लिए बीमाकर्ता द्वारा पुनर्बीमाकर्ता को अदा किए गए पुनर्बीमा अधिमूल्य से अधित्याग कमीशन या पुनर्बीमा कमीशन काटा जाता है, इस शर्त के अध्वधीन कि, केंद्रीय कर, राज्य कर, संघराज्य क्षेत्र कर और एकीकृत कर बीमाकर्ता द्वारा पुनर्बीमाकर्ता को देय कुल पुनर्बीमा अधिमूल्य पर अदा किया जाता है, जिसमें उक्त अधित्याग कमीशन या पुनर्बीमा कमीशन शामिल है।”।

अदा कर या
पुनरीक्षित निविष्टि
कर ज़मा रकम
का प्रतिदाय नहीं
होगा।

४०. सभी अदा किये गये कर या, पुनरीक्षित निविष्टि कर ज़मा रकम का प्रतिदाय नहीं होगा जो इस प्रकार अदा नहीं किया गया है या पुनरीक्षित नहीं किया गया है, इस अध्यादेश की धारा ७ सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में बनी रही थी।

व्यक्तव्य

वस्तु और सेवा कर परिषद द्वारा अपने बैठक में वस्तु और सेवा कर विधियों में संशोधन करने की आवश्यकता से संबंधित विभिन्न निर्णय लिये गये हैं। तदनुसार, वित्त अधिनियम, २०२४ (सन् २०२४ का ८) और वित्त (क्रमांक २) अधिनियम, २०२४ (सन् २०२४ का १५) द्वारा केंद्रिय वस्तु और सेवा कर, २०१७ (सन् २०१७ का १२) में संसद द्वारा से संशोधित किया गया है। उपर्युक्त बैठकों में वस्तु और सेवा कर परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों का कार्यान्वयन करने और केंद्रिय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, २०१७ और महाराष्ट्र वस्तु और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (सन् २०१७ का महा. ४३) के उपबंधों को लागू करने में एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से, महाराष्ट्र वस्तु और सेवा कर अधिनियम, २०१७ में संशोधन करना इष्टकर है।

२. महाराष्ट्र वस्तु और सेवा कर अधिनियम, २०१७ के प्रस्तावित संशोधन **अन्य बातों के साथ** निम्न के लिए उपबंध करते हैं, अर्थात् :—

(एक) धारा २ की, उप-धारा (६१) की प्रतिस्थापित करना है, ताकि मुख्य कार्यालय द्वारा, तीसरे पक्ष से प्राप्त की गयी निविष्टि सेवा प्रक्रिया के संबंध में निविष्टि कर ज़मा रकम के वितरण के लिये निविष्टि सेवा वितरक प्रक्रिया को अनिवार्य बनाया जा सके परंतु, मुख्य कार्यालय और शाखा कार्यालय या दोनों या अनन्य रूप से एक या अधिक शाखा कार्यालयों के लिये जिम्मेवार माना जा सकेगा ;

(दो) धारा ९ में संशोधन करना है, ताकि मानव उपभोग के लिए अल्कोहल युक्त शराब के निर्माण करने के लिए उपयोग किये जानेवाले असंक्रमित अतिरिक्त अल्कोहल या परिशोधित स्पिरिट पर राज्य कर उद्ग्रहीत नहीं किया जा सके ;

(तीन) धारा ११क को निविष्टि करना है, ताकि सरकार को राज्य कर के गैर-उद्ग्रहण या कम उद्ग्रहण को नियमित करने की शक्ति मिल सके, जहाँ वह समाधानी है कि, ऐसा गैर-उद्ग्रहण या कम उद्ग्रहण सामान्य व्यवहार का परिणाम था ;

(चार) धारा १३ की, उप-धारा (३) में संशोधन करना है, ताकि सेवाओं में आपूर्ति का समय विनिर्दिष्ट किया जा सके, जिस मामले में संरक्षित प्रभार आपूर्ति के मामलों में सेवाओं के प्राप्तकर्ता द्वारा बीजक जारी किया जाना आवश्यक है ;

(पाँच) धारा १६ की, उप-धारा (५) निविष्टि करना है, ताकि विद्यमान उप-धारा (४) के लिये अपवाद बनाया जा सके और यह उपबंध किया जा सके कि, उक्त उप-धारा के अधीन बीजक या नामे नोट के संबंध में, वित्तीय वर्ष २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० और २०२०-२१ के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा ३९ के अधिन कोई विवरणी में निविष्टि कर ज़मा रकम लेने के लिए हकदार होगा, जिसे तीस नवम्बर २०२१ तक दायर किया जायेगा ;

(छह) धारा १७ की, उप-धारा (५) में संशोधन करना है, ताकि केवल वित्तीय वर्ष २०२३-२४ तक की माँगों के लिए, उक्त अधिनियम की धारा ७४ के अधीन अदा किये गये कर के संबंध में निविष्टि कर ज़मा रकम की अनुपलब्धता को निर्बंधित किया जा सके ;

(सात) धारा ३० की, उप-धारा (२) में नवीन परन्तुक निविष्टि करना है, ताकि रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण प्रतिसंहरन करने के लिए शर्तें और निर्बंधन विहित करने के लिए राज्य सरकार को, सशक्त किया जा सके ;

(आठ) धारा ३९ की, उप-धारा (३) में संशोधन करना है, ताकि चाहे कोई कटौती उक्त महीने में की गयी है या नहीं की गयी है के बावजूद स्रोत में कर कटौती करने के लिये आवश्यक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रत्येक महीने के लिये विवरणी इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य किया जा सके ;

(नौ) धारा ७० की, उप-धारा (१क) निविष्टि करना है, ताकि उक्त अधिकारी द्वारा जारी समन के अनुपालन में समुचित अधिकारी के समक्ष, समन प्राप्त हुए व्यक्ति की ओर से उपस्थित होने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधि को समर्थ किया जा सके ;

(दस) धारा ७३ की, उप-धारा (१२) निविष्ट करना है, ताकि वित्तीय वर्ष २०२३-२४ तक की अवधि से संबंधित कर का विनिश्चयन करने के लिए उक्त धारा की लागू करना निर्बंधित किया जा सके।

(ग्यारह) धारा ७४ की उप-धारा (१२) निविष्ट करना है, ताकि वित्तीय वर्ष २०२३-२४ तक की अवधि से संबंधित कर का विनिश्चयन करने के लिए, उक्त धारा को लागू करना निर्बंधित किया जा सके ;

(बारह) धारा ७४क को निविष्ट करना है, ताकि वित्तीय वर्ष २०२४-२५ से संबंधित कर अदा नहीं किया गया है या कम अदा किया गया है या गलत तरीके से प्रतिदाय किया गया है या किसी कारण के लिए निविष्ट कर ज़मा रकम का गलत तरीके से ला गयी है या उपयोग किया गया है, का विनिश्चयन करने के लिए उपबंध किया जा सके ;

(तेरह) धारा १०७ की, उप-धारा (६) में संशोधन करना है, ताकि अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने के लिए राज्य कर में पूर्व-निक्षेप की अधिकतम रकम पच्चीस करोड़ रुपयों से बीस करोड़ रुपयों तक घटाई जा सके ;

(चौदह) धारा १०९ में संशोधन करना है, ताकि सरकार को अपील अधिकरण द्वारा सुनवाई किये जानेवाले उस मामलों के प्रकार अधिसूचित करने के लिए सशक्त किया जा सके ;

(पंद्रह) धारा ११२ की उप-धारा (१) और (३) में संशोधन करना है, ताकि सरकार को अपील अधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए दिनांक अधिसूचित करने और अपील अधिकरण के समक्ष अपील या आवेदन दायर करने के लिए, पुनरीक्षित समय-सीमा के उपबंध करने के लिए सशक्त किया जा सके ;

(सोलह) धारा ११२ की, उप-धारा (८) में संशोधन करना है, ताकि अपील अधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए पूर्व-निक्षेप की अधिकतम रकम विवाद में विद्यमान कर के बीस प्रतिशत से दस प्रतिशत तक घटाने और राज्य कर में पूर्व-निक्षेप के रूप में देय अधिकतम रकम भी पचास करोड़ रुपयों से बीस करोड़ रुपयों तक घटाई जा सके ;

(सत्रह) धारा १२२ की, उप-धारा (१ख) में संशोधन करना है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य परिचालकों, जो उक्त अधिनियम की धारा ५२ के अधीन स्रोत में कर संग्रहण करना आवश्यक है, को उक्त उप-धारा लागू करना निर्बंधित किया जा सके।

(अठारह) धारा १२२क को निविष्ट करना है, ताकि धारा १४८ के अधीन अधिसूचित विशेष प्रक्रिया के उल्लंघन में कृत्य करने के इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत न किए गए किसी मशीन के लिए एक लाख रुपयों की, शास्ति का प्रावधान उपबंधित किया जा सके ;

(उन्नीस) धारा १२८क को निविष्ट करना है, ताकि गलती से प्रतिदाय होने के संबंध में माँग नोटीस को छोड़कर वित्तीय वर्ष २०१७-१८, २०१८-१९ और २०१९-२० के लिए उक्त अधिनियम की धारा ७३ के अधीन जारी माँग नोटीस के संबंध में ब्याज और शास्ति का सशर्तत्यजन करने के उपबंध किया जा सके ;

(बीस) धारा १७१ की, उप-धारा (२) में संशोधन करना है, ताकि सरकार को, वह दिनांक अधिसूचित करने के लिए सशक्त किया जा सके जिससे उक्त धारा के अधीन प्राधिकरण मुनाफाखोरी रोधी मामलों के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं करेगा ;

(ईक्कीस) अनुसूचि तीन में परिच्छेद ९ और १० को निविष्ट करना ;

(बाईस) धारा १० की, उप-धारा (५), धारा २१, धारा ३५ की, उप-धारा (६), धारा ४९ की उप-धारा (८), धारा ५० की, उप-धारा (१), धारा ५१ की, उप-धारा (७), धारा ६१ की, उप-धारा (३), धारा ६२ की, उप-धारा (१), धारा ६३, धारा ६४ की, उप-धारा (२), धारा ६५ की, उप-धारा (७), धारा ६६ की, उप-धारा (६), धारा ७५, धारा १०४ की, उप-धारा (१), धारा १०७ की, उप-धारा (११) और १२७ में संशोधन करना है, ताकि प्रस्तावित नई धारा ७४क के संदर्भ निगमित कर सके।

(३) चूँकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र वस्तु और सेवा कर अधिनियम, २०१७ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्यः कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

मुंबई,

दिनांकित ६ अक्टूबर २०२४।

सी. पी. राधाकृष्णन,

महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

ओम प्रकाश गुप्ता,

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

(यथार्थ अनुवाद)

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।